



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2015/फाल्गुन 13, 1936

No. 73]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2015/PHALGUNA 13, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

मुंबई, 26 फरवरी, 2015

गणपूर्ति

1. श्री टी.एस.बालासुब्रमण्यन्, सदस्य (वित्त)
2. श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

(फरवरी 2015 के 13वें दिन पारित)

प्रकरण सं. टीएमपी/23/2013/एमबीपीटी।—मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के दरमान (एसओआर) के सामान्य संशोधन हेतु मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में इस प्राधिकरण ने प्रकरण सं. टीएमपी/23/2013/एमबीपीटी में दरमान अधिसूचित करते हुए 2 जनवरी, 2015 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश भारत का राजपत्र असाधारण (भाग-III खंड 4) में राजपत्र सं. 19 के माध्यम से 19 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि 19 जनवरी, 2015 को अधिसूचित दरमान और इसकी शर्तों में कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं। त्रुटियों और उनमें की जाने वाली शुद्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	दरमान का संदर्भ	जैसा अधिसूचना में प्रकाशित है						निम्नानुसार पढ़ा जाये						
		क्र. सं.	प्रभार्य पोत	प्रति जीआरटी की दर		एक ही पोत के बारे में देय राशि कितनी बार देय	क्र. सं.	प्रभार्य पोत	प्रति जीआरटी की दर		एक ही पोत के बारे में देय राशि कितनी बार देय			
				तटीय (रु.) में	विदेश-गामी (अम. डालर) में				तटीय (रु.) में	विदेश-गामी (अम. डालर) में				
1.	खंड 2.1 (क) क्र. सं. 02 (ख) 'गोदी' के अंतर्गत तटीय			पहले 30000 जीआरटी के लिए रु.. 349803/-....		पहले 30000 जीआरटी के लिए रु. 349812/-....								
2.	खंड 2.16 (पत्तन देयताएँ) क्रम सं. 4			तटीय (रु.) में	विदेश-गामी (अम. डालर) में			तटीय (रु.) में	विदेश-गामी (अम. डालर) में		तटीय (रु.) में	विदेश-गामी (अम. डालर) में		

		4	पत्तन सीमाओं के भीतर प्रचालित अंतर्देशीय पोत	5.016	0.1833	यह देय राशि 1 माह में केवल एक बार देय है।		4	पत्तन सीमाओं के भीतर प्रचालित अंतर्देशीय पोत	5.016	--	यह देय राशि 1 माह में केवल एक बार देय है।
3क	खंड 1.1(iii)	तटीय पोत का अर्थ होगा कोई भी पोत जो केवल भारत में किसी भी पत्तन स्थान से भारत में ही किसी भी अन्य पत्तन या स्थान के बीच व्यापार में लगा हो और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस हो।	तटीय पोत का अर्थ होगा, कोई भी पोत जो केवल भारत में किसी भी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी भी अन्य पत्तन या स्थान के बीच व्यापार में लगा हो और जिसके पास पोत परिवहन महा निदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस हो।									
3ख	खंड 2.17 नोट्स	-लागू नहीं-	एमबीपीटी के दरमान के खंड 2.17 के अंतर्गत, निम्नलिखित नया नोट, नोट सं. 9 के रूप में डाला गया है। 9. पत्र सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी, दिनांक 4 सितम्बर, 2014 के जरिये पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी महापत्तनों पर तटीय पोतों की वरीयता वर्तिंग पर मार्गदर्शी: (i) 'तटीय पोत' को, भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच अनन्य रूप से व्यापार में लगे और पोत परिवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस धारक किसी पोत के रूप में परिभाषित किया गया है। (ii) महा पत्तन कम से कम एक वर्ष में शुष्क बल्क/सामान्य कार्गो वाले तटीय पोतों को वरीय/प्राथमिक वर्तिंग प्रदान करेंगे ताकि कार्गो के मूल स्थान और उसके अंतिम गंतव्य का विचार किये बिना शिपर्स सामान का भारत में एक पत्तन से दूसरे पत्तन तक परिवहन कर सके। यह महापत्तनों में, तटीय तापीय कोयले के प्रहस्तन के लिए, यदि कोई हो, समर्पित वर्ष के अतिरिक्त होगा। (iii) कंसेशन एग्रीमेंट और निजी टर्मिनलों पर विडो वर्तिंग के प्रचलित आवंटन तथा पत्तनों द्वारा प्रचालित कंटेनर वर्थों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी महापत्तन विशिष्ट (विनिर्दिष्ट) खिड़की के जरिये तटीय कंटेनर पोतों को प्राथमिक (वरीय) वर्तिंग प्रदान करेंगे। (iv) पीओएल/लीक्विड कार्गो के बारे में विभिन्न पत्तनों में ऐसी वरीयताओं के संबंध में प्रचलित परम्पराएँ/व्यवहार जारी रखे जा सकते हैं। (v) तटीय पोत जिन्हें वरीय वर्तिंग प्रदान की जानी है, को वरीय वर्तिंग प्रभार भुगतान नहीं करने होंगे। (vi) यदि वह (तटीय पोत) पत्तन की सामान्य वर्तिंग नीति के अंतर्गत पात्र है तो उपरोक्तानुसार वरीयता पर वर्थ किए गए तटीय पोत के अतिरिक्त तटीय पोत की वर्तिंग पर कोई पावंडी नहीं होगी। (vii) इस बात का विचार किए बिना कि तटीय पोत वरीयता आधार पर या अन्यथा वर्थ किया गया था, उसे तटीय दरों पर ही पत्तन प्रभारों का भुगतान करना होगा। (viii) तटीय कार्गो के प्रस्तान को और अधिक सुचारू बनाने की दृष्टि से पत्तनों को सीमा शुल्क वंशित क्षेत्र के बाहर तटीय कार्गो के लिए अनन्य वर्थ भंडारण क्षेत्र और (निकासी) द्वारा चिह्नित करने की संभावनाएँ तलाशनी चाहिए। (ix) महापत्तन, किसी विशेष पत्तन में तटीय पोतों को वर्थ किये जाने हेतु एक निश्चित/साफ-साफ समय सीमा निर्धारित करेंगे जिसके भीतर तटीय पोत वर्थ किए जाएंगे। यह समय सीमा कार्गो और वर्थ पर निर्भर करते हुए भिन्न हो सकती है। प्रत्येक महापत्तन (इस विषय में) व्यापक परिश्रम करेगा और उस ऊपरी समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक ट्रैड नोटिस जारी करेगा जिस समय सीमा के भीतर किसी तटीय पोत को पत्तन में वर्थ किया जाएगा। तटीय कंटेनर पोतों को विनिर्दिष्ट खिड़की के जरिये वरीयता वर्तिंग के संबंध में महापत्तनों को पीपीपी प्रचालकों के साथ विस्तृत चर्चा करनी चाहिए और तटीय (कंटेनर) पोतों के लिए विनिर्दिष्ट खिड़की को सार्वजनिक करना चाहिए। उपरोक्त कवायद (परिश्रम) और उसको सार्वजनिक/प्रकाशित करने का काम इन मार्गदर्शियों के जारी किये जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। (x) पत्तन में एमआईएस, तटीय और विदेशगामी पोतों (और) कार्गो के लिए अलग-अलग डाटा इकट्ठा करेगा। इस प्रकार इकट्ठा किया									

		गया डाटा पत्तन में मानीटर किया जाएगा और पत्तन के साथ आईपीए को आंतरिक रूप से तथा मंत्रालय को, तीर्य तथा विदेश गामी पोतों के लिए अलग-अलग प्रारूपों में सूचित किया जाएगा।	
4.	अध्याय VII अनुसूची 7.2	पत्तन न्यास हार्डी अथवा पोत घाट पर कहीं भी निर्माण किए जा रहे या फिट किये जा रहे/रही नौकाओं, टोनियों, हॉडियों, रैफटों, पॉन्टूनों, टैक बार्जों, डम्प बार्जों और अन्य जलयानों समेत पोतों से निर्माण/मरम्मत के प्रयोजन से हार्ड पर अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से, रु. 5.65 प्रति जीआरटी प्रति दिन की दर से प्रभार लिया जाएगा।	पत्तन न्यास हार्डी अथवा पोत घाट पर कहीं भी निर्माण किए जा रहे या फिट किये जा रहे/रही नौकाओं, टोनियों, हॉडियों, रैफटों, पॉन्टूनों, टैक बार्जों, डम्प बार्जों और अन्य जलयानों समेत पोतों से निर्माण/मरम्मत के प्रयोजन से हार्ड पर अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से, रु. 5.97 प्रति जीआरटी प्रति दिन की दर से प्रभार लिया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2014(315)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

Mumbai, the 26th February, 2015

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

(Passed on this 13th day of February 2015)

No. TAMP/23/2013/MBPT.—This Authority had passed an Order on 2 January, 2015, notifying the Scale of Rates in case No.TAMP/23/2013/MBPT relating to the proposal received from the Mumbai Port Trust (MBPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR). This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 19 January 2015 vide Gazette No.19.

2. It has been noticed that some errors have occurred in the SOR and its conditionalities notified on 19 January, 2015. The details of the errors and the corrections to be made are detailed below:

Sl. No.	Reference to the SOR	As appeared in the Notification					To be read as given below				
		Sl. No.	Vessels chargeable (in ₹)	Rate of per GRT		Due how often chargeable in respect of same vessels	Sl. No.	Vessels chargeable	Rate of per GRT		Due how often chargeable in respect of same vessels
2.	Section 2.16 (Port Dues), Sl. No. 4			Coastal (in ₹)	Foreign - going (in US \$)				Coastal (in ₹)	Foreign - going (in US \$)	
1.	Section 2.1 (A), Sl. No. 2 (b)- Coastal under Column 'Docks'	4.	Inland vessels operating within port limits	5.016	0.1833	The due is payable once in the same month	4.	Inland vessels operating within port limits	5.016	---	The due is payable once in the same month
3a.	Section 1.1 (iii).	'Coastal Vessel' shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having valid coastal licence issued by the competent authority.					"Coastal vessel" shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the Director General of Shipping/ competent authority."				
3b.	Section 2.17, Notes	--- Not Applicable ----					The following new Note is introduced as Note No. 9 under Section 2.17 of the Scale of Rates of MBPT: 9. Guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Ports issued by the Ministry of Shipping vide letter No.PT-11033/51/2014-PT dated 4 September, 2014:				

			(i). “Coastal vessels” is defined as any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping/competent authority. (ii). Major ports shall accord priority berthing, at least on one berth, to dry bulk/ general cargo coastal vessels to enable shippers to transport goods from one port in India to another port in India irrespective of origin and final destination of the cargo. This would be in addition to dedicated berth, for handling of Coastal Thermal Coal already existing in Major Ports, if any. (iii). All Major Ports shall accord priority berthing through specific window to coastal container vessels keeping in view the concession agreements and existing allotment of window berthing at the private terminals and availability of container berths operated by the ports. (iv). In respect of POL/Liquid cargo tankers, existing practices regarding such priorities as prevalent in various ports may continue. (v). Coastal vessels which are be accorded priority berthing shall not be liable to pay priority berthing charges. (vi). There will be no restrictions on berthing of coastal vessel, in addition to the coastal vessel berthed on priority as above, if the same is eligible under normal berthing policy of the port. (vii). A coastal vessel shall be liable to pay port charges on coastal rates notwithstanding whether it was berthed on priority or otherwise. (viii). Ports should explore the possibilities of earmarking exclusive berth, storage areas and gates for coastal cargo outside the custom bonded area of the Ports to further facilitate movement of coastal cargoes. (ix). Major Ports shall clearly work out the time limit within which a coastal vessel would be berthed in a particular port. This time limit may differ depending on the cargo and berth. Each Major Port should carry out a detailed exercise and issue a trade notice clearly indicating the upper time limit within which a coastal vessel would be given a berth in the port. As regards priority berthing through a specific window to coastal container vessels, Major Ports should have a detailed discussion with the PPP operator and publish the specific window for coastal container vessels. The above mentioned exercise and publication should be completed within 30 days from the date of issue of these guidelines. (x). The MIS in the Port should capture data for coastal and foreign vessels cargoes separately. The data so captured shall be monitored and reported internally in the port as well as to IPA and Ministry in separate formal for coastal and foreign vessels.
4.	Chapter VII Schedule 7.2	Vessels including boats, tonies, hodies, rafts pontoons, tank barges, dump barges and other craft being constructed or fitted out in the Port Trust hards or anywhere on wharf will be charged ₹ 5.65 per day per GRT from the date of occupation of the hard for the purpose of construction/repairing.	Vessels including boats, tonies, hodies, rafts pontoons, tank barges, dump barges and other craft being constructed or fitted out in the Port Trust hards or anywhere on wharf will be charged ₹ 5.97 per day per GRT from the date of occupation of the hard for the purpose of construction/repairing.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/2014(315)]